## बजट आंकड़ों में

**10 लाख करोड़ डॉलर**

आठ साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य पर पहुंचाने का इरादा

**12 लाख करोड़ रुपये**

प्रत्यक्ष कर संग्रह जो वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपये था

**एक लाख करोड़ रुपये**

जनवरी 2019 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह

**कृत्रिम मेधा को बढ़ावा**

लोगों को कृत्रिम मेधा और संबंधित प्रौद्योगिकी का लाभ देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा। राष्ट्रीय कृत्रिम मेधा केंद्र के साथ-साथ उत्कृष्टता केंद्र बनाकर इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता वाले नौ क्षेत्रों की पहचान की गई है।

**शिक्षा, आईसीडीएस के लिए ज्यादा पैसा**

वित्त वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 32,334 करोड़ रुपये थी। एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के आवंटन 27,584 करोड़ रु. कर दिया गया है जबकि 2018-19 के संशोधित अनुमान में यह 23,357 करोड़ रुपये है।

**बंजारों की सुध**

गैर अधिसूचित घुमंतू और बंजारा समुदायों की पहचान का काम पूरा करने के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। ये ऐसे समुदाय हैं जिनका अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकरण नहीं किया गया है। इन समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

**मालवहन और जलमार्गों पर जोर**

पूर्वोत्तर में कंटेनर कार्गो की आवाजाही शुरू की जाएगी। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में सुधार किया जाएगा। पहली बार कोलकाता और वाराणसी के बीच जलमार्ग के जरिये कंटेनर मालवहन की व्यवस्था शुरू की गई है।

**पशुपालन की चिंता**

गो संसाधनों के सतत अनुवांशिक उन्नयन और गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। आयोग गायों से संबंधित कानून और कल्याणकारी योजनों के कारगर क्रियान्वयन का काम भी देखेगा। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया।

### बजट प्रभाव

बजट में कई क्षेत्रों के लिए सौगात दी गई है। किसानों और मध्य वर्ग को रियायत मिलने से खर्च योग्य आय बढ़ेगी और इससे रिटेल, एफएमसीजी और वाहन जैसे कई क्षेत्रों को अच्छी बिक्री दर्ज करने में मदद मिलेगी

"मध्य वर्ग, छोटे कारोबारी और किसान आर्थिक वृद्धि की जीवनरेखा हैं। बजट में लाखों सपनों को पूरा करने की कोशिश की गई है"

**गौतम अदाणी**, चेयरमैन, अदाणी समूह

# उपभोक्ता और वाहन कंपनियां भरेंगी फर्राटा

### उभोक्ता क्षेत्र/वाहन

एफएमसीजी, रिटेल और वाहन कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि खर्च योग्य आय बढ़ने से मांग में सुधार आएगा

**इस** साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट ने एफएमसीजी, रिटेल और वाहन क्षेत्रों में कई कार्यकारी अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में कृषि चिंताओं को दूर करने और ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं की आय में सुधार लाने के मकसद से कई उपायों की घोषणा की गई।

प्रमुख रियायतों में छोटे किसानों के लिए आश्वस्त आय, 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि और पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए दो प्रतिशत की ब्याज छूट शामिल हैं। वेतनभोगी वर्ग के लिए, पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है, मानक छूट 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है, जबकि 40,000 रुपये तक की ब्याज आय को टीडीएस से मुक्त किया गया है।

कंपनी अधिकारियों और विश्लेषकों दोनों का कहना है कि इन उपायों से खर्च योग्य आय में सुधार आएगा, जिसके परिणामस्वरूप एफएमसीजी और वाहन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। हाल के समय में मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री की रफ्तार धीमी रही है और अब इसमें तेजी आने की संभावना है। दूसरी तरफ, रिटेल क्षेत्र में भी, स्टोरों में अधिक आवक दिखने और उसके परिणामस्वरूप बिक्री बढ़ने की संभावना है।

गोदरेज कंज्यूमर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विवेक गंभीर कहते हैं, 'यह 'खपत-केंद्रित' बजट है और इससे एफएमसीजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 'इससे आम आदमी की महत्ता बढ़ेगी और मांग में तेजी आएगी।'

मारुति सुजूकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव का कहना है, 'इस बजट में किसी को निराश नहीं किया गया है। इसमें ऐसा कोई कर या उपकर नहीं लगाया गया है जिससे लोगों की आय में कमी आएगी। इसके बजाय, इसमें ऐसे कई प्रस्ताव किए गए हैं जिनसे लोगों की आय बढ़ेगी, जो अच्छा संकेत है। हालांकि, अंतरिम बजट होने की वजह से रियायतें उस वक्त बदल सकती हैं जब इस साल के अंत में अंतिम बजट की घोषणा की जाएगी।'

डाबर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी सुनील दुग्गल का कहना है, 'बजट में मध्य वर्ग के पास अधिक खर्च योग्य आय होने का वादा किया गया है। इसमें लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार की भी कोशिश की गई है, जो जरूरी है। इसमें जो अन्य पेशकश स्वागत योग्य है, वह है सरकार की दीर्घावधि सुधारों के प्रति वचनबद्धता। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को 24 घंटे के अंदर पूरा करने और रिफंड के तुरंत भुगतान ऐसे निर्णय हैं जिनसे एक नए भारत की नींव तैयार होगी।'

दुग्गल का कहना है कि 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कम कॉरपोरेट कर (25 प्रतिशत) का लाभ मुहैया कराकर छोटे एवं मझोले उद्योगों को भी लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। यह सीमा पहले 50 करोड़ रुपये से कम थी। उनका कहना है कि इससे कर चोरी घटेगी, कंपनियों के पास निवेश योग्य अधिक रकम मौजूद होगी। वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी कृष अय्यर कहते हैं, 'बजट में मध्य वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होने से खपत बढ़ेगी। बजट में इंडिया और भारत के बीच अंतर पाटने की भी कोशिश की गई है।'

कंपनियों के अधिकारियों और विश्लेषकों, दोनों का कहना है कि इन उपायों से खर्च योग्य आय में सुधार आएगा, जिसके परिणामस्वरूप एफएमसीजी और वाहन क्षेत्रों में मांग में इजाफा होगा

**रियायतों की घोषणा**

- प्रमुख रियायतों में छोटे किसानों के लिए आश्वस्त आय, 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि और पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए दो प्रतिशत की ब्याज छूट शामिल है
- कंपनी अधिकारियों और विश्लेषकों दोनों का कहना है कि इन उपायों से खर्च योग्य आय में सुधार आएगा, जिसके परिणामस्वरूप एफएमसीजी और वाहन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी

# बजट प्रावधान से बुलंद होगी किफायती मकान की बुनियाद

### रियल एस्टेट

सबको घर देने की प्रधानमंत्री की पहल से रियल्टी क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव

**पांच** लाख रुपये तक की सालाना आय पर कर छूट देने की घोषणा से संकट से जूझ रहे 200 अरब डॉलर के भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र को उबारने में बड़ी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको घर देने की पहल को भी इस कदम से बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1.52 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषा में कहा, '2014-18 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1.53 करोड़ मकान बनाए गए हैं।' इस योजना के लिए बजट में 25,853 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2018 के 26,405 करोड़ रुपये था यानी इस मद में करीब दो फीसदी कम आवंटन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आवंटन में कमी मुख्य रूप से इसलिए की गई है क्योंकि अब इस योजना के तहत ज्यादातर मकान निजी क्षेत्रों के

किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार को अपनी पहल पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है।'

उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होने से किफायती मकानों की मांग बढ़ सकती है, जिससे खासतौर पर उत्तर भारत में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति 6.5 लाख रुपये सालाना कमाई करता है तो वह सालाना 2 लाख रुपये तक दस साल के लिए ऋण लेने का पात्र होगा।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, 'प्रत्यक्ष कर में बदलाव से खासतौर पर मध्य आय वर्ग के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे होंगे। इसके अलावा मानक कटौती में बढ़ोतरी से भी मकान खरीदना असान हो सकता है, जिससे इस क्षेत्र में मांग बढ़ सकती है।'

एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के अनुसार किफायती कीमत खंड वाले आवासीय इकाइयों की मांग हाल के समय में बढ़ी है और इस खंड में नई परियोजनाएं भी आ रही हैं। इस खंड में 5 लाख रुपये से 40 लाख रुपये कीमत के मकान आते हैं।

उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि अगले एक साल में 150 किफायती आवासीय परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। वर्तमान में करीब 100 किफायती आवासीय परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके साथ ही डेवलपर नई परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी भी कर रहे हैं। टाटा रियल्टी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी संजय दत्त ने कहा, 'इससे किफायती आवासीय क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने का रास्ता साफ होगा।'

# उद्योग जगत.. थोड़ी खुशी, ज्यादा की आस

### बजट पर चर्चा

कॉरपोरेट दिग्गजों का मानना है कि खपत वृद्धि की घोषणा के अलावा बजट में उनके लिए और कुछ खास नहीं है

**निर्माताओं** और सेवा प्रदाताओं के लिए किसी प्रत्यक्ष लाभ की अनुपस्थिति में खपत में सिर्फ संभावित तेजी का वादा ही भारतीय उद्योग जगत के लिए काम की बात है। उनका कहना है कि पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट एक चुनाव-पूर्व और मतदाताओं को लुभाने वाला बजट है।

कई कॉरपोरेट दिग्गज सुबह 11 बजे से लगभग आधा घंटा पहले ही दिल्ली के ली मैरीडियन होटल में एकत्रित हो गए थे। वे बजट का सीधा प्रसारण देखने के लिए बड़े स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। इस अवसर पर उद्योग संस्था भारतीय उद्योग संघ के बैनर तले वहां कई वरिष्ठ अधिकारी और मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। कई कॉरपोरेट दिग्गज उदास दिख रहे थे। हीरो एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल से लेकर आईटीसी होटल्स के मुख्य कार्याधिकारी दीपक हक्सर भी शांतचित्त रह कर गोयल का पूरा भाषण सुनते रहे। लगभग दो घंटे बाद वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हो गया, लेकिन इन लोगों के मूड में खास बदलाव नहीं आया।

गरीब किसानों को आय सहायता से लेकर नौकरीशुदा लोगों के लिए कर राहत जैसी पेशकशें मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई हैं। किसानों को आय सहायता से जहां 12 करोड़ किसानों को फायदा होने की बात कही गई है वहीं कर राहत से सालाना पांच लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी लोगों को कर चुकाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वित्त मंत्री ने देश के सबसे बड़े करदाता वर्ग कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए कोई अच्छी खबर सुनाने से परहेज किया।

हालांकि इससे बड़ी कंपनियों को आश्चर्य नहीं हुआ है। उनके अनुसार, वे बजट में कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए किसी बड़े फायदे की उम्मीद नहीं कर रही थीं और अधिक कमाई वाली कंपनियों के लिए बजट में कोई विपरीत कर नहीं लगाया गया है।

एक प्रमुख निर्माण कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'हालांकि यह चुनाव-पूर्व बजट है और आम आदमी को लुभाने के लिहाज से अच्छा है।'

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजित बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित रियायतों से

**भारतीय उद्योग जगत ने बजट में खपत वृद्धि को सराहा है**

खपत बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था और उद्योग को मदद मिलेगी।

वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) में जमा हुए कॉरपोरेट दिग्गजों की भी अलग राय नहीं है। कॉरपोरेट कर में वृद्धि नहीं किया जाना उनके लिए राहत की सांस है। भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राजन भारती मित्तल ने कहा, '500,000 रुपये तक कमाने वाले लोगों के लिए कर छूट की वजह से वस्तुओं और ड्यूरेबल्स की खपत में तेजी आएगी।' उन्हें इससे भी राहत मिली है कि सभी कर आकलन कर अधिकारी के साथ किसी डायरेक्ट इंटरफेस के बजाय ऑनलाइन के जरिये होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी कर का आकलन रिटर्न फाइलिंग के 24 घंटे के अंदर किया जाएगा और यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

एचएसबीसी इंडिया की मुख्य कार्याधिकारी एवं कंट्री हेड नैना लाल किदवई ने कहा कि गैर-बिकी संपत्ति पर कल्पित आय के लिए कर छूट का लाभ मौजूदा एक वर्ष की अवधि से बढ़ाकर दो वर्ष के लिए लागू किया गया है जिससे डेवलपरों को राहत मिलेगी।

## बीएस सूडोकू 3348

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | 3 | | |
| 1 | | 6 | 5 | | 3 | 8 | | |
| | 3 | | 1 | | | | | 2 |
| | | 9 | | | | 6 | 4 | 3 |
| | | | 4 | | 7 | | | |
| 4 | 2 | 8 | | | | 7 | | |
| 9 | | | | | 8 | | 6 | |
| | | 4 | 9 | | 1 | 2 | | 5 |
| | | 2 | | | | | | 7 |

परिणाम संख्या 3347

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |

**कैसे खेलें?**

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम

★★★☆☆

# ग्रामीण भारत को राहत, उद्योग को भी मिलेगी ताकत

### कॉरपोरेट जगत

सरकार ने अर्थव्यवस्था के दो सबसे मजबूत स्तंभों- किसानों और मध्य वर्ग का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है

**आम** चुनाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अब तक सरकार की नीतियों का इस वर्ग तक लाभ नहीं पहुंच पाया था। कारोबारी नेतृत्व का कहना है कि सबसे बड़ी राहत छोटे किसानों और 5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले वेतनभोगी लोगों को दी गई है।

हालांकि बड़े कारोबारियों को कर में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। एक कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को तर्कसंगत बनाकर बजट के बाद थोड़ी राहत दी जा सकती है। आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा, 'वित्त मंत्री ने हमारी अर्थव्यवस्था के दो सबसे मजबूत स्तंभों – किसानों और मध्य वर्ग का दिल जीतने का भरसक प्रयास किया है। बजट में होश तथा जोश का संतुलन कायम रखते हुए खपत को बढ़ावा दिया गया है, वहीं ग्रामीण इलाकों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार की कोशिश की गई है।'

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि चुनावों को देखते हुए पहले लोक-लुभावन बजट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसमें अपव्यय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'मध्य वर्ग और किसानों को राहत देने से मैं खुश हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था को दिवालिया करने के जोखिम से भी बचा गया है।'

मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि संकट में फंसे किसानों को आज की घोषणाओं से काफी लाभ होगा। छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक नकद सहायता उनकी आय को बढ़ाने और गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में अच्छा कदम है। हिंदुजा समूह के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने कहा, 'इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ने से मुद्रास्फीति नहीं बढ़नी चाहिए और न

**मुख्य कार्याधिकारियों ने बजट को किसानों और मध्य वर्ग के लिए मददगार करार दिया है**

ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े।'

हिंदुजा ने कहा, 'रक्षा एवं पूंजीगत व्यय में ज्यादा आवंटन से विनिर्माण उद्योग और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 फीसदी पर रखने की बात कही गई जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान से थोड़ा अधिक है। लेकिन ज्यादा घाटे से अगर वस्तुओं और सेवाओं के सृजन को बढ़ावा मिलता है तो इसका आर्थिक विकास पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।'

एस्सार समूह के निदेशक प्रशांत रुइया ने कहा कि बजट से निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खपत मांग बढ़ने से सभी उद्योगों का विकास होगा। रुइया ने कहा, 'प्रत्यक्ष कर में रियायत से न केवल मध्य वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि उद्योग को भी फायदा होगा क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इससे मांग में इजाफा होगा। इसी तरह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से भी दीर्घावधि में उद्योग को लाभ होगा।'

रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन उद्योगों के लिए उत्साहजनक है, खास तौर पर रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में। भारत फोर्ज के सीएमडी बाबा कल्याणी ने कहा, 'मेरा मानना है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। इसमें एमएसएमई का भी स्वागत है क्योंकि बड़े उद्योगों को सहारा देने में इन उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन कदमों से देश में रोजगार का भी सृजन होगा।'

व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से वेतनभोगी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे खपत मांग में भी इजाफा होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विवेक गंभीर ने कहा, 'लेकिन समय की मांग उत्पादक रोजगार सृजन करने पर ध्यान देने की है जिससे युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।'